“हक मांगो अभियान”

15 जून, 2017

ज्ञापन

1. आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी,

   प्रधानमंत्री, भारत सरकार,

   नई दिल्ली

2. आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर,

   मुख्यमंत्री, हरियाणा

किसान अधिकार मांग पत्र

हरियाणा व भारत के किसान 'हक मांगो अभियान' के माध्यम से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों से अपना हक़ मांगते हैं। केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में खट्टर सरकार जब से सत्ता में आई हैं, तभी से किसानों व गांव में रहने वाले खेत मजदूर/कृषि आधारित काम धंधों से गुजारा करने वाले किसान, खेत मजदूर, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व छोटे दुकानदार के साथ लगातार अनदेखी व सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे देश व प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, **“खट्टर व नरेंद्र मोदी– दोनों हैं किसान विरोधी।”**

केंद्र व हरियाणा सरकार किसान तथा खेत मजदूरों की निम्नलिखित मांगें पूरो करे :–

1. **वायदे के मुताबिक 'फसल की लागत + 50 % मुनाफा' दें**

   हम प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर को याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश व प्रदेश की जनता से किसानों को फसलों की लागत + 50 % मुनाफा देने का वायदा किया था। (पृष्ठ 44, भाजपा घोषणापत्र, 2014 लोकसभा)। सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा सरकार ने 20 फरवरी, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र देकर यह बयान दिया कि लागत + 50% मुनाफा समर्थन मूल्य पर नहीं दिया जा सकता। यह जनता के साथ सीधी धोखाधड़ी है और देश के किसान चाहते हैं कि भाजपा अपना चुनावी वायदा पूरा करे।

   भाजपा के शासनकाल में किसानों को फसलों के उचित दाम भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान जीरी/धान की 1121 /1509 किस्मों पर ₹ 5500 प्रति क्विंटल तक का भाव मिला था, जो कि पिछले साल ₹ 2200 क्विंटल में पिटी। बासमती धान कांग्रेस सरकार में ₹ 6000 क्विंटल तक बिकी, जो पिछले साल भाजपा की अनदेखी के चलते ₹ 2800 से ₹ 3000 क्विंटल में पिटी। यही हाल कपास/नर्मा/बाजरा/गन्ना/पापुलर फसलों के दामों की है, क्योंकि भाजपा सरकार ने किसानों से घोर अन्याय किया है। मज़दूरी, डीज़ल, खाद, बीज, कीटना"ाक दवाईयां व अन्य चीजों में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन किसान से किया गया वायदा भाजपा ने पूरा नहीं किया, जिससे देश के किसान आंदोलित हैं।

2. **कर्जे व आत्महत्या की खेती से मिले मुक्ति। सोमांत, लघु किसान, खेत मजदूर, कृषि पर आधारित काम धंधों में लगे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व छोटे दुकानदार का कर्जा माफ किया जाए।**

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार के किसान विरोधी रवैये से देश का किसान– खेत मजदूर लगातार हताश होता जा रहा है। हालत यह हो गई है कि 2014 में 12,360 किसान/कृषक/खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। 2015 में 12,602 तथा 2016 में 14,000 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की आशंका व्यक्त की गई है, जो कि बेहद चिंताजनक है।

हर रोज देश के 35 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों को अंतरिम सहायता देने के लिए किसानों– मजदूरों के कर्जे माफ होने चाहिए। हरियाणा के किसान 'हक मांगों अभियान' के अंतर्गत यह मांग करते हैं कि सीमांत, लघु किसान, खेत मजदूर, कृषि पर आधारित काम धंधों में लगे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व छोटे दुकानदारों का सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ किया जाए।

3. **'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' प्राईवेट बीमा कंपनियों को मुनाफा देने का छलावा। किसान आपदा राहत दोबारा शुरु की जाए।**

किसान समुदाय पर कुठाराघात करते हुए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया और किसानों को पहले से मिल रही आपदा राहत व्यवस्था बंद कर दी। यह फसल बीमा योजना सरकार की चहेती 10 से अधिक चुनिंदा और निजी इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। इसमें किसानों से जबरन प्रीमियम वसूला जा रहा है।

यह इससे साबित होता है कि सिर्फ खरीफ, 2016 में बीमा कंपनियों को दी गई बीमा प्रीमियम राशि ₹17,185 करोड़ है, जबकि किसान को दिया गया मुआवजा मात्र ₹ 6,808 करोड़ है, यानि केवल एक फसल में ही बीमा कंपनियों द्वारा ₹ 10.376 करोड़ का मुनाफा कमा लिया गया। अकेले जींद जिले में किसान से फसल बीमा के नाम पर ₹ 35 करोड़ वसूले गए, जबकि मुआवज़ा मिला मात्र ₹ 57 लाख।

हमारी मांग है कि सरकार को जबरन प्रीमियम वसूली तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए तथा जो किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें किसी आपदा से फसल का नुकसान होने पर किसानों को कम से कम ₹ 25000 प्रति एकड़ की राहत सुनिश्चित करना चाहिए।

4. **कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। देश व प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा डीज़ल पर बढ़ाई गई एक्साईज ड्यूटी, वैट व अन्य कर की वृद्धि वापस हो।**

सच यह है कि 16 मई, 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें लगभग 55% से अधिक कम हुई हैं। भाजपा सरकार ने पेट्रोल की एक्साईज़ ड्यूटी में 34% तथा डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी 140% बढ़ोत्तरी की है। यह किसान से विश्वासघात है।

चुनाव परिणाम के दिन यानि 16 मई, 2014 को कच्चे तेल की कीमत 107.09 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी, जो कि 3 साल बाद 12 मई, 2017 को 47.42 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है। लेकिन डीज़ल की कीमत कम होने की बजाए ₹ 56.71 से बढ़कर ₹ 67.35 हो गई है। सच्चाई यह है कि अगर कच्चे तेल की 55 % घटी हुई लागत का फायदा किसानों व आम आदमी को दें, तो आज के दिन डीज़ल व पेट्रोल की कीमतें निम्नलिखित होनी चाहिए :–

	मौजूदा कीमत (रुपया/लीटर)	कीमत होनी चाहिए (55% गिरी कीमतों पर)
पेट्रोल	**₹ 68.09**	**₹ 32.14**
डीज़ल	**₹ 67.35**	**₹ 25.52**

भाजपाई लूट का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 01 अप्रैल, 2014 को डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी ₹ 3.56 प्रति लीटर थी। भाजपा सरकार ने इसे 3 साल में 11 बार बढ़ाकर ₹17.33 प्रति लीटर कर दिया। इसी प्रकार 01 अप्रैल, 2014 को पेट्रोल पर एक्साईज़ ड्यूटी ₹ 9.48 प्रति लीटर थी।

भाजपा सरकार ने 3 साल में बढ़ाकर इसे ₹ 21.48 प्रति लीटर कर डाला। **सच्चाई यह है कि केंद्रीय भाजपा सरकार ने मई, 2014 से मई, 2017 के बीच में कच्चे तेल की कीमतों में 107.09 अमेरिकी डॉलर से कम होकर 47.42 अमेरिकी डॉलर तक कम होने से 2,33,000 करोड़ की कमाई जनता से कर ली।**

केवल इतना ही नहीं, हरियाणा की खट्टर सरकार ने डीज़ल पर वैट 9.24% से बढ़ाकर 17.22% कर डाला। इसी प्रकार पेट्रोल पर भी 21% से वैट को बढ़ाकर 26.25% कर डाला।

5. **किसान की 'ब्याज माफी स्कीम' खत्म करने की भाजपाई साजिश का पर्दाफाश।**

कांग्रेस सरकार ने साल 2006—07 के बजट से किसान को ₹ 3 लाख तक मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर 7 प्रति"ात निर्धारित कर दी तथा समय पर ऋण चुकाने वाले किसान को 3 प्रति"ात ब्याज का मुनाफा देते हुए ब्याज की दर को 4 प्रति"ात तक घटा दिया। यह इस प्रकार है :—

2009-10 -	1%
2010-11 -	2%
2011-12 -	3%
2012-13 -	3%
2013-14 -	3%
2014-15 -	3%
2015-16 -	3%
2016-17 -	3%

(https://www.nabard.org/content.aspx?id=602)

साल 2017—18 में भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे से इस ब्याज राहत स्कीम को बंद करने का निर्णय ले लिया। यह बैंकों की 9 मई, 2017 की चिट्ठी से साफ है, जिसकी प्रति संलग्नक A1 संलग्न है। मंदसौर, मध्यप्रदेश में 6 किसानों की भाजपा सरकार द्वारा निर्मम हत्या के बाद व पूरे दे"ा में किसान आंदोलन तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के चलते केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा आनन—फानन में कल 14 जून, 2017 को मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई गई, तथा ब्याज राहत स्कीम को दोबारा बहाल किया गया।

क्या भाजपा की केंद्र व प्रांतीय सरकारें बताएंगी कि ब्याज राहत स्कीम को 01 अप्रैल, 2017 से 14 जून, 2017 के बीच क्यों बंद किया गया? इस किसान विरोधी साजिश के लिए कौन जिम्मेदार है?

क्या भाजपा इस 'ाडयंत्रकारी कार्य के लिए माफी मांगेगी।

6. **हरियाणा के बिजली संकट के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार। सरकार ने बिजली की जरूरत न बताकर बिजली के 5 कारखाने बंद कर दिए लेकिन किसान मजदूर बिजली की कमी से भारी परेशान है।**

प्रदे"ा में चल रहे बिजली संकट और जनता को हो रही परेशानी के लिए प्रदे"ा की भाजपा सरकार सीधी रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने बिजली पैदा करने वाले पांच बिजली संयंत्र बंद कर रखे हैं। प्रदेश के शहरों व गांव में बिजली के घोषित व अघोषित कट लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता बिजली की भारी कमी झेल रही है।

प्रदेश सरकार ने 1270 मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले पांच बिजली कारखाने बंद कर रखे हैं, जिनमें से तीन पानीपत में, एक यमुनानगर में व एक हिसार के खेदड़ गांव में है। यमुनानगर में केवल एक बिजली संयंत्र में बिजली बनाई जा रही है, जबकि 300 मेगावॉट का बिजली संयंत्र 10 जून से बंद है। इसी

प्रकार पानीपत में केवल एक 250 मेगावॉट बिजली का संयंत्र चल रहा है, जबकि 210 मेगावॉट वाले 2 बिजली संयंत्र पिछले एक महीने से बंद हैं और 250 मेगावॉट वाला बिजली संयंत्र हाल ही में बंद किया गया है। हिसार के खेदड़ में केवल एक बिजली संयंत्र काम कर रहा है, जबकि 300 मेगावॉट वाला दूसरा बिजली संयंत्र 22 मई से बंद है। इसके अलावा सरकार ने झाड़ली के एनटीपीसी बिजली संयंत्र में से भी प्रदेश के हिस्से की बिजली लेने से इंकार कर रखा है, जो कि जनता के साथ सीधा धोखा है।

हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट करे कि एक तरफ तो उसने बिजली की मांग न होने के नाम पर बिजली संयंत्र बंद कर रखे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान मजदूर व जनता को इस भारी गर्मी में बिजली के बिना रहने पर मज़बूर होना पड़ रहा है। बिजली के कारखाने पुनः चालू कर खेत–खलिहान व गांव तथा शहरों को सुनिश्चित बिजली सप्लाई दी जाए।

7. **<u>SYL के पानी पर हरियाणा के किसानों का अधिकार। भाजपा राजधर्म निभाए।</u>**

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक केंद्रीय भाजपा सरकार SYL नहर का निर्माण करवाए तथा SYL का पानी हरियाणा के किसान को मिले। आपसी चर्चा के बहानों को छोड़ें तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कर राजधर्म निभाएं।

निवेदक

हरियाणा किसान खेत मजदूर कांग्रेस व हरियाणा कृषक समाज